

**CORRECTIONS OF ANSWER TO
USQ NO. 1451 DATED 7-6-1971
RE : PLASTIC CORNEA
GRAFTING**

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND HEALTH AND FAMILY PLANNING (SHRI UMA SHANKAR DIKSHIT) : In answer to Lok Sabha Unstarred Question No. 1451 replied on the 7th June, 1971, it was mentioned in the last portion of the reply that "the patient can now recognise faces". Subsequent enquiries have revealed that this is not correct. One of the patients, Shri Hazari Lal who was operated at Dr. Rajendra Prasad Centre for Ophthalmic Sciences, was blind since childhood. His pre-operative vision was restricted to mere perception of light. Plastic corneal grafting was done on him on the 28th of April and at the end of 5 weeks it found that there were no signs of graft rejection and graft had remained clear. So far as visual improvement is concerned, it was only marginal. He can appreciate hand movements close to the face but this is not considered significant improvement.

The operation was not planned to restore vision. The real objective of the plastic cornea grafting is for the present to ensure the acceptance of the polymer by the human eye and its preservation as a clear medium. At the same time, there may be a marginal benefit in so far as vision is concerned.

It is not the intention to try these polymers on cases for marked degree of restoration of vision for the present. Further trials will be continued with a view to ascertain whether acceptance and clarity rate is statistically significant.

12.02 hrs.

**CALLING ATTENTION TO MATTER
OF URGENT PUBLIC
IMPORTANCE**

**Reported US decision to supply Arms to
Pakistan**

श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव (कटिहार) :
अध्यक्ष महोदय, मैं अविनाशकारी प्रतिक्रिया के निम्नलिखित विषय की ओर विशेष ध्यान

का ध्यान दिलाता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि इसके बारे में वे बतलाव दें :

"राष्ट्रपति निक्सन के वैयक्तिक अधिकारों के अधीन पाकिस्तान को 3.50 करोड़ डालर मूल्य के सस्त्रास्त्र देने का संयुक्त राज्य अमरीका का कथित निश्चय।"

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI SWARAN SINGH) : Government have seen the text of the statement made by Senator Church on July 7, 1971, that an estimated \$35 million worth of military equipment is still in the arms pipeline for delivery to Pakistan. On 8th July, 1971, a State Department Spokesman stated that "the average approximate figure over the last five fiscal years has been in the order of \$10 to 15 million a year."

Senator Church is a well informed Senator and has been taking great interest in the question of arms supply by USA to different countries. It is possible that his figure may not be far from correct. In any case, amounts in dollars do not give a clear indication of the nature and quantum of military equipment involved. Equipment purchased from certain governmental sources is valued much below the normal market price. All spare parts which may cost very little can reactivate deadly weapons.

Government shares the concern of all sections of the House about the continued supply of military equipment by USA to Pakistan. I would like to assure the House that our views on the subject have been conveyed in unequivocal terms to the US Government.

Government feel that supply of arms to Pakistan by any country in the present context amounts to condonation of genocide in Bangla Desh and encouragement to the continuation of the atrocities by the military rulers of Pakistan. It also amounts to an intervention on the side of the military rulers of West Pakistan against the people of Bangla Desh. We have left US Government in no doubt about the dangerous implications of such a policy on the situation in Bangla Desh and on the peace and stability of the sub-continent and the region as a whole.

श्री आन्ध्रप्रदेश प्रसाद भास्कर : अध्यक्ष महोदय, अमरीका जोकि एक साम्राज्यवादी देश है उसने अभी कोरिया में या वियतनाम में जो अपनी फौजें भेजी या वहाँ पर जो हस्तक्षेप किया उसके बारे में अमरीका यही बराबर कहता रहा कि हम लोकतन्त्र की रक्षा के लिए, मानव मूल्यों की रक्षा के लिए और बिस्तारवादी चीन के इरादों को परास्त करने के लिए ही वहाँ पर सैनिक और सैनिक सामग्री भेज रहे हैं लेकिन आश्चर्य के साथ कहना पड़ता है कि अमरीका बंगला देश में जहाँ पर ये तीनों फॅक्टर्स मौजूद हैं—वहाँ पर लोकतंत्र को प्रतिष्ठित करने के लिए मुजीबुर्रहमान की अबामी शींग पार्टी सशर्षरत है—लोकतन्त्र और मानव मूल्यों की रक्षा नहीं करना चाहता जहाँ पर नरसंहार हो रहा है और पाकिस्तान के विस्तारवादी इरादों के कारण इतना अधिक शोषण हुआ है कि जिसके कारण आर्थिक असंतुलन पैदा हो गया है और वहाँ की सात करोड़ जनता पाकिस्तान के खिलाफ संघर्षरत है। ऐसी स्थिति में अमरीका हमको बार-बार यह आश्वासन देता रहा, बार-बार यह हितोपदेश देता रहा ब्यय पर खर्चा कम करो, आप रक्षा भार कम करो और दूसरी तरफ वह पाकिस्तान को आधुनिकतम हथियारों से लस करने का प्रयास करता रहा। इतना ही नहीं, अभी हमारे विदेश मंत्री ने अमरीका जा कर के भारत की भावनाओं से और भारत सरकार की नीति से अमरीका को परिचित कराने का प्रयास किया लेकिन इसमें कोई सफलता किसी का नहीं मिली, इस बात का रहस्योद्घाटन वहीं के सिनेटर फ्रैंक बर्ष ने किया कि राष्ट्रपति निक्सन के आदेश से 3 करोड़, 55 लाख डालर, जोकि लगभग सबा 26 करोड़ रुपये होता है, के मूल्य के अस्त्रास्त्र पाकिस्तान को भेजे जा रहे हैं। वी जहाज पहले पाकिस्तान को भेजे जा चुके हैं, फुल: और भेजे जा रहे हैं। इतना ही नहीं, 1972 के वित्तीय वर्ष में अमरीका ने जो अस्त्र शोधों को अस्त्र सहायता या इस प्रकार की अन्य

सहायता की योजना बनाई है उसमें सबसे अधिक राशि, लगभग 52 करोड़ डालर की सैनिक सामग्री पाकिस्तान को दी जाएगी। ऐसी स्थिति में मैं जानना चाहता हूँ, सारा सदन आज अंधेरे में है कि अमरीकी राष्ट्रपति निक्सन के विशेष दूत हेनरी किसिंगर भारत आये और उन्होंने भारत के प्रधान मन्त्री, विदेश मन्त्री, रक्षा मन्त्री और यहाँ तक कि आर्मी के प्रधान सेनापति से भी बातचीत की लेकिन इसको अन्धकार में रखा गया है, आज सारा सदन और देश इस बात से अनभिज्ञ है कि क्या हेनरी किसिंगर ने यहाँ पर आ करके भारत सरकार को किसी प्रकार का आश्वासन दिया है कि भविष्य में हम इस प्रकार का काम नहीं करेंगे ? या बंगला देश की समस्या के लिए, वहाँ पर स्वातंत्र्य संग्राम की भावना के अनुकूल हम पाकिस्तान के ऊपर कोई दबाव डालेंगे ? क्या इस प्रकार की कोई बातें उन्होंने कही हैं ?

दूसरी बात मैं विदेश मन्त्री से वह जानना चाहता हूँ कि अमरीका की जो भारत विरोधी नीति रही है, जिस प्रकार से वह पाकिस्तान में अस्त्रास्त्र का प्रसार लयाकर भारत की सुरक्षा को खतरे में डालना चाहता है, ऐसी स्थिति में क्या हम विदेश मन्त्री से आशा करें और मैं भारत सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि अमरीका अगर अस्त्रास्त्र देकर हमारी स्वतंत्रता के ऊपर आघात पहुँचाना चाहता है, हमारे देश की एकता और एकात्मता के खिलाफ अगर कदम उठाने की साजिश करता है तो क्या हम अमरीका से किसी प्रकार का अनुदान नहीं लेने चाहे उसके लिए हमें भले ही वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़े और हो सकता है कि हमारी विकास की गति धीमी चले परन्तु उससे एक बात अशक्य होगी कि हम आत्मनिर्भर बनेंगे और दुनिया के सामने एक सम्मानित राष्ट्र के रूप में निखरेंगे।

अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, अभी तक तो अमरीका पाकिस्तान को अस्त्रास्त्रों की

धरूपति करता था लेकिन सन्डे टाइम्स आफ इंडिया में 10 तारीख को एक न्यूज प्रकाशित हुई है जिसमें वहाँ के सिनेटर टूनी, मैं उनको बन्धुवाद देना चाहता हूँ, ने एक रहस्योद्घाटन किया है और वह यह है कि अभी तक तो केवल शस्त्रास्त्र दिए जा रहे थे लेकिन अब अमरीका के जहाज जोकि अन्न लेकर कराची बन्दरगाह पर आते हैं वे जहाज पाकिस्तानी फौज को लेकर अटगांव में, ढाका में पहुंचाते हैं। इस प्रकार से अमरीका प्रत्यक्ष रूप से बंगला देश में जो स्वातंत्र्य आन्दोलन चल रहा है उसको दबाने के लिए मंदाप में आ गया है। क्या भारत सरकार उसकी इस मनोवृत्ति के खिलाफ, क्या भारत सरकार उसकी इस नीति के खिलाफ, या उसने इस प्रकार से जो हमको छोड़ा है या हमारी भावना पर आघात पहुंचाया है, इसके लिए कोई कारगर कदम उठायेगी।

SHRI SWARAN SINGH : I agree with the first part of his speech in which he has analysed the situation and voiced the concern of the county and of the House about the continued supply of arms by the US Government to Pakistan. At the end, he has asked two or three specific questions to which I will confine my replies.

First of all, he asked whether any assurance that the US would not supply arms to Pakistan was given by Dr. Kissinger when he was here in Delhi. I would like to say that Dr. Kissinger was on a fact-finding mission and he did not give any assurance of that type.

SHRI INDRAJIT GUPTA (Alipore) : Did he ask for any such assurance ?

SHRI SWARAN SINGH : We have asked at a level much higher than Dr. Kissinger's for such an assurance, but it is not forthcoming.

SHRI INDRAJIT GUPTA : What kind of facts did he find out here ?

SHRI SWARAN SINGH : It is for him to answer, not for me.

SHRI SAMAR GUHA (Coimbatore) : Did

the Minister acquaint the House with the dialogue ?

SHRI SWARAN SINGH : The second question was whether Dr. Kissinger had said that he would exercise any pressure on Pakistan to discontinue the military action in Bangla Desh.

SHRI P. K. DEO (Kalahandi) : Is the Minister satisfied ?

SHRI SWARAN SINGH : I am not satisfied at all.

This matter had been taken up very strongly by us with the US Government in Washington, and they have been saying that they would take the matter up with Pakistan, but we will not accept it unless there is any result. On the other hand, the atrocities in Bangla Desh continue and as I told Shri P. K. Deo, I am not at all satisfied with whatever action might have been taken in this respect by the US Government.

SHRI SAMAR GUHA : Are you satisfied with your own action, the action you are taking about Bangla Desh ?

MR. SPEAKER : I do not like such interruptions.

SHRI SWARAN SINGH : We can defer that. What we are discussing today is something different.

MR. SPEAKER : The hon. Minister need not pay attention to him.

SHRI SWARAN SINGH : I agree that the US policy to arm Pakistan dating back to the year 1954 is the main source of building up the military potential of Pakistan. From 1954 to 1965, military equipment worth 1,700 to 2,000 million dollars has reached Pakistan from US sources. That has enabled her to build up her military potential, and the continuation of the current supply, particularly after the military action in Bangla Desh, is something which is of great concern to us, in view of the fact that several countries have stopped the supply of all arms to Pakistan after events in Bangla Desh took the turn they have.

We have, therefore, been constantly pressing the United States Government to

[Shri Swaran Singh]

give up their plan of continued supply of arms to Pakistan even though the licences for these might have been issued earlier to 25th March when the military action in Pakistan started, but we have not succeeded.

About the statement by Senator Tunney to which the hon. Member referred, we have been informed by the U.S. Embassy today that no U.S. flag ship was carrying Pakistani troops. This is what they have told us today.

AN HON. MEMBER : They may deny it tomorrow.

SHRI SWARAN SINGH : If they deny it tomorrow, I will make that known tomorrow. This is the statement they make now.

श्री फूल चन्द बर्मा (उज्जैन) : अध्यक्ष महोदय, मैंने विदेश मंत्री जी का बक्तव्य बड़े ध्यानपूर्वक सुना और उसको सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि हमारी सरकार कुछ तथ्य छिपाना चाहती है, वास्तविकता को सदन के आगे लाना नहीं चाहती है।

जहाँ तक दुनिया के बड़े देशों का सवाल है, दुनिया का कोई भी बड़ा देश यह नहीं चाहता कि भारतवर्ष एक अक्षितशाही राष्ट्र के रूप में दुनिया के सामने खड़ा हो। और यही रवैया बंगला देश की समस्या के मामले में अमरीका का रहा है। मंत्री महोदय ने अपने बक्तव्य में कहा है 35 मिलियन डालर की पाकिस्तान को सहायता देने की बात सीनेटर चर्च ने अमरीकन सीनेट में कही है तो मैं जानना चाहता हूँ कि वह सत्य है अथवा नहीं है? और इसकी खोज-बीन के लिए हमारे रूताबास ने कोई विशेष प्रयत्न किया भी है कि नहीं। और मंत्री जी ने अपने बक्तव्य में स्वीकार किया है कि यह ठीक के करीब है। मंत्री महोदय अपने काम में काफी रुचि रखते हैं इसलिए मैं उनसे यह जानना चाहता हूँ कि वास्तव में कितनी सहायता दी गई? 35 मिलियन डालर की सहायता के आंकड़े सही हैं, अथवा गलत हैं।

दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूँ कि जब संसद का सत्र बाधू है और अमरीका से श्री किस्सन के सलाहकार, श्री किर्तिजर यहाँ पर आये थे तो उनसे चर्चा के दौरान सदन को विश्वास में क्यों नहीं लिया गया? सदन को अंधेरे में रखा गया?

दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या हमारी सरकार इस बात के लिए तैयार है कि अमरीका का जो इस प्रकार का भारत विरोधी रवैया है उसके विरोध स्वरूप हम अमरीका स्थित भारतीय राजदूत को वापस बुलाने के लिए तैयार हैं क्या?

SHRI SWARAN SINGH : I have already said that the figure of 35 million dollars given in Senator Church's statement appears to be nearer the correct figure. I hesitate to say so because this may be revised upwards by the United States as they have been giving different figures from time to time. To be quite candid to the House I cannot give the exact figure because even the United States spokesmen have been changing their figures from time to time.

About the second question, I have already stated that the United States Embassy have told us that American flag ships have not been used for transporting Pakistani troops.

DR. RANEN SEN (Barasat) : What is your information?

SHRI SWARAN SINGH : I have no information to the contrary.

SHRI INDRAJIT GUPTA : They may use the vessels of other countries to carry grains to Pakistan, and those vessels can carry troops. Why this emphasis on flag ships?

SHRI SWARAN SINGH : The question was based on Senator Tunney's statement which was about American ships?

About the talks that took place between Dr. Kissinger and the Government of India's Ministers, including the Prime Minister, myself and the Defence Minister, I have al-

ready told the House that he is an adviser of the President of the United States. As such he may advise the President but he is not the policy-maker himself. There was an exchange of views and an exchange of information. There is no question of keeping the House in the dark because normally on anything that is talked with foreign representatives no statement giving all the details are made, unless there is anything of high importance. It is not customary, nor is it in our interest that we should publicise everything that takes place at the diplomatic level.

The last part of his speech contained a suggestion ; we have no intention of adopting that suggestion.

श्री जगन्नाथ राव जोशी (शाजापुर) : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय का बन्तब्य सुन कर मुझे रवीन्द्रनाथ टैगोर का एक महत्वपूर्ण वाक्य याद आ गया :

We read the world wrong and say that it deceives us.

वास्तव में अमरीका हो, रूस हो या बड़ी ताकतें हें, उन का रबैया अपने देश के बारे में क्या है यह छिपी हुई बात नहीं है। अमरीका में प्रजातन्त्र है इस लिए सेनेटर्स बोलते हैं, रूस जैसे कम्युनिस्ट देश में प्रजातन्त्र न होने की वजह से चोरी छिपे क्या होता है उसका पता नहीं लग सकता। 1954 में जब अमरीका ने पाकिस्तान को हथियार देने का निर्णय किया सिंगाटो और सेन्टो के मेम्बर के नाते, तब कम से कम एक बहाना था।

It is a sort of a fig leaf to oppose communism.

1954 में कम से कम यह बात कही जा सकती थी, किन्तु 1965 के बाद जब कम्युनिस्ट कट्टी रूस, कम्युनिस्ट कट्टी चाइना, पाकिस्तान को मदद दे रहे हैं और अमरीकी हथियारों का प्रयोग भारत के खिलाफ हुआ तब यह बहाना भी नहीं रहा। सारे देश पाकिस्तान को हथियार दे रहे हैं और स्वयम् मन्त्री महोदय भूम कर भाये, अध्यक्ष नारायण जी भी भूम कर भाये हैं और लोगों का निष्कर्ष यही है कि जो

दुनिया के बड़े देश कहलाते हैं : इंग्लैंड, फ्रांस, अमरीका, रूस, चीन आदि, वह कोई भी इस बंगला देश के मामले में पाकिस्तान पर दबाव डाल कर जो शरणाधी भाये हैं वह लौट जायें ऐसी परिस्थिति निर्माण करने में सहायता देना तो दूर रहा :

They are exacerbating the situation.

यह स्वयम् वहाँ के सेनेटर का कहना है।

यह जो सारा स्टेटमेंट है उसका निचोड़ यही है कि :

"We have left the United States Government in no doubt about the dangerous implications of such a policy on the situation in Bangla Desh".

But the Minister has left us also in doubt about the explosive situation.

यानी शरणाधी लोगों के वापस जाने की दृष्टि से जो हमारे सुझाव हैं बंगला देश को मान्यता देने और उनको सहायता देने के वह आपको मज़ूर नहीं है, यह बात समझ में आ गई, किन्तु दुनिया के देशों की दबाव डाल कर वह वापस जायें ऐसी परिस्थिति निर्माण करने की कोई इच्छा भी उनकी नहीं है। यही नहीं, दस दिन पहले मेरे पास एक पत्र आया है जिस में बतलाया गया है कि छठ नौ साल के लड़के लड़कियां हंगर मार्च में हिस्ता ले रही हैं और जगह-जगह जा कर बन्दा इकट्ठा कर रही हैं। यह सारा बन्दा लाहौर भेजा गया है इस विचार से कि बंगला देश में अचामी लीग ने जो तिजु-एशन पैदा की है उसमें पश्चिमी पाकिस्तान के लोग ही रिफ्यूजी बन गये हैं। उनके लिए अमरीका में पैसा इकट्ठा हो रहा है और वह वहाँ जा रहा है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी है ?

अमरीका का जो रबैया है उस के देखने के बाद मैं कहना चाहता हूँ It will not do simply to express our concern.

यह सब कुछ होने के बाद हम क्या करना चाहते हैं ? अगर हमारा सुझाव मान्य नहीं है

[श्री जगन्नाथ राव जोशी]

कि पाकिस्तान में सिंचुएशन किस तरह से नार्मल हो कि शरणाधी वापस जायें तो फिर इस दिशा में सरकार का ठोस कदम क्या है ?

SHRI SWARAN SINGH : Sir, in the first part of his opening statement, he tried to equate the United States and the USSR in the matter of supply of arms. I would like to say categorically that he cannot do that, because, whereas the United States Government have clearly said that they are not stopping the supply of arms to Pakistan even after the happenings in Bangla Desh, the USSR Government and their spokesmen have made clear statements that they have not supplied any arms or even spares to Pakistan particularly after April, 1950. That is the latest statement that they have made.

SHRI JAGANNATHRAO JOSHI : They are treating India and Pakistan on the same footing. It has appeared even in today's papers.

SHRI SWARAN SINGH : How is that on the same footing in the matter on supply of arms ? (Interruption).

अध्यक्ष महोदय : जब मिनिस्टर साहब जवाब दे रहे हैं तब इस तरह से आपस में बात नहीं करनी चाहिये ।

SHRI SWARAN SINGH : His second question also suffers from a somewhat similar complex because he has tried to say that perhaps in 1954, the United States had some excuse to supply arms to Pakistan on the ground that it was meant to check communism. He might have been taken in by that argument, because we knew fully well that the tanks and several other types of equipment that the United States was supplying to Pakistan could never be used against communism. We knew that the only place where they could be used was perhaps the Indo-Gangetic plain against India. So we had never any doubt, and I do not see as to why the hon. Member has laboured this point and said that this was perhaps an excuse in 1954 which apparently he appears to gulp. I would warn him that he should not adopt that attitude. We know that in

1954, these arms were supplied to Pakistan against us, and the same policy continues. So, there was no question of any valid excuse in 1954, as there is none today, except their own desire, as they say, to continue to give support to Pakistan in the matter of military equipment.

He has ultimately asked as to what are our plans in relation to Bangla Desh. This question relates to the supply of arms. We had a whole day's debate on Bangla Desh, and I do not intend to repeat my speech.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (स्वालयर) : अध्यक्ष महोदय, जब से हमारे विदेश मंत्री वाशिंगटन की यात्रा करके लौटे हैं प्रति दिन अमरीका सरकार की नीति के बारे में ऐसे तथ्यों का उद्घाटन हो रहा है जो भारत के लिये एक चक्के की तरह से है । मैं यह तो नहीं कहता कि यह विदेश मन्त्री के प्रवास का परिणाम है, लेकिन मैं यह जरूर कहूंगा कि यह बात बड़ी सफाई से हमारे विदेश मन्त्री को मान लेनी चाहिए कि वह वाशिंगटन को प्रभावित करने में विफल रहे हैं । जब वह वाशिंगटन से लौट कर आये तब पालम हवाई अड्डे पर बड़े खुश थे । उनकी खुशी से हम भी साक्षीदार थे । उन्होंने यह आश्वासन दिलाया कि अमरीका की नीति बदल गई है, फिर पता लगा कि जहाज जा रहे हैं । पहले दो जहाज और फिर तीन जहाज और फिर पांच जहाज । आज कहा जा रहा है कि पाइप लाइन में जितनी मदद है वह सब पहुंचेगी । पता नहीं पाइप लाइन कितनी लम्बी है । यह भी पता नहीं लगता कि उस पाइप लाइन में कितने हथियार हैं, कितने पुर्जे हैं । अमरीका के सेंटेटरों के बक्तव्यों से यह सब पता लगता जा रहा है और इसके लिए हमें उनको बधाई भी देनी चाहिये लेकिन उसके साथ-साथ हमें अपने दूतावास को भी अधिक सक्रिय करने की आवश्यकता है । सेंटेटर वर्क ने जो कुछ कहा है न्यू यार्क टाइम्स ने उसकी पुष्टि की है । मैं विदेश मन्त्री से पूछना चाहता हूँ कि क्या अब

सच है कि अमरीका के स्टेट डिपार्टमेंट ने, डिफेंस डिपार्टमेंट ने राष्ट्रपति को शिफारिश की थी कि इस समय पाकिस्तान को कोई हथियार न दिये जायें लेकिन राष्ट्रपति निश्चयन ने अपने ही स्तर पर इसका निर्णय लिया है कि अमरीका से हथियार जायेंगे ? मैं जानना चाहता हूँ कि इसके बारे में भारत सरकार का क्या कहना है ।

श्री जय प्रकाश नारायण ने यह कहा है कि वाशिंगटन में दो सरकारें चल रही हैं । पेंटागान सरकार के भीतर सरकार है । शायद हमारे विदेश मन्त्री महोदय ने अपने प्रवास के दौरान पेंटागान से कोई प्रेमालाप नहीं किया और अगर किया हो तो यह सदन उसकी जानकारी प्राप्त करना चाहेगा । हम यह भी जानना चाहते हैं कि 35 मिलियन डालर की जो सहायता पाठप लाइन में है, उसके प्रतिरिक्त अमरीका पाकिस्तान को और कितनी सहायता देने जा रहा है ? इसके बारे में भी क्या हमें सैनेटर्स के वक्तव्यों पर निर्भर रहना पड़ेगा ? अभी खबर आई है और उसके साथ ही सुरक्षा मन्त्रालय के प्रवक्ता का खडन भी आया है कि अमरीका 1972 के लिए 5 मिलियन डालर हमें दे रहा है और पांच मिलियन डालर पाकिस्तान को दे रहा है । हम उनसे एक तिहाई बढ़े हैं । इसके साथ यह भी आ रहा है कि पांच-पांच मिलियन डालर के साथ-साथ ढाई मिलियन डालर की सहायता और दी जा रही है पाकिस्तान को । मैं चाहता हूँ कि विदेश मन्त्री महोदय सदन को तथा सारे देश को विश्वास में लें । प्रतिदिन समाचारपत्रों में पढ़ कर हम यहाँ कॉलिंग स्टेशन सूचना दें यह कोई सदन की प्रतिस्था के लिए भ्रष्टाचार नहीं लगता है । विदेश मन्त्री महोदय को एक ब्यारेबार तथ्यों का समावेश करने का बन्तव्य देना चाहिए । अगर वह इसके लिए समय चाहते हैं तो सदन समय देने के लिए तैयार है । लेकिन दुकड़ों में सूचना भ्राना ठीक नहीं है । मैं जानना चाहता हूँ कि अमरीकी सरकार के रवैये और

इरादों के बारे में उनका क्या मत है ? मुझे उनके वक्तव्य के प्रतिम परिच्छेद पर आपत्ति है । विदेश मन्त्री महोदय कहते हैं कि वे हथियार बंगला देश के नर सहार को और अधिक बढ़ावा देंगे । यहाँ तक तो मैं उनसे सहमत हूँ । लेकिन मैं एक कदम आगे जाकर कहना चाहता हूँ कि बंगला देश में नर सहार करने के लिए पाकिस्तान के पास पहले से ही काफी हथियार हैं । ये हथियार जो आ रहे हैं वे पाकिस्तान को हिन्दुस्तान पर कभी भी फौजी हमला करने के लिए प्रेरित करने की दृष्टि से आ रहे हैं । यह हमला कहीं भी हो सकता है । जम्मू काश्मीर में, राजस्थान में, गुजरात में भी हो सकता है आखिर इस समय हथियार देने का मतलब क्या है, अमरीका का इरादा क्या है ? अभी विदेश मन्त्री महोदय कह रहे थे कि हमें रूस और अमरीका को एक घरातल पर रखने की आवश्यकता नहीं है । लेकिन अभी आज के अल्लबारों में इस्वीस्तिया का समाचार छपा है कि रूस के नेता हमें भी कह रहे हैं कि धीरज धरो और पाकिस्तान को भी कह रहे हैं कि धीरज धरो । क्या यह भारत और पाकिस्तान को एक ही स्तर पर रखना नहीं है ? पाकिस्तान ने जो कुछ बंगला देश में किया है वह अकेले अपने नागरिकों के साथ अन्याय नहीं है, अत्याचार नहीं है, उससे हमारी सुरक्षा भी खतरे में पड़ गई है और मैं कहना चाहता हूँ कि एक सिविल एग्रेसन करने के बाद सत्तर लाख लोगों को हमारे देश में बकलना यह सिविल एग्रेसन है और पाकिस्तान मिलटरी एग्रेसन की तैयारी कर रहा है और ये हथियार उस मिलटरी एग्रेसन में जो भारत के खिलाफ किया जाएगा, काम में लाए जायेंगे । अब मैं दो तीन प्रश्न पूछना चाहता हूँ ।

पहला मेरा सवाल है कि क्या सरकार ने अमरीका को अभी तक कोई लिखित विरोध पत्र भेजा है । मैं लिखित विरोध पत्र की बात कह रहा हूँ जपानी अर्थात् कर्ष की नहीं । कूटनीतिक

[श्री अटल बिहारी वाजपेयी]

केब लिखित विरोध पत्र का एक अलग ही महत्व होता है।

डा० किंसागर यहां आए। वह सलाहकार हैं। उनका काम सलाह देना है। गलत सलाहें भी वह दे सकते हैं। वह सलाह वहां देगे और तथ्यों का यहां पता लगायेंगे। मैं जानना चाहता हूं कि क्या हमने उनको इस बात के लिए आमंत्रित किया कि वह थोड़े से रिफ्यूजी कैम्प जा कर देखें। अगर ऐसा किया जाता तो उनको तथ्य मिल जाते। उनको लोगों के चेहरों पर भय और आतंक की जो कहानियां लिखी हैं वे पढ़ने को मिस जाती और विदेश मन्त्री को उनको समझाने की जरूरत नहीं थी। अगर हम ने उनको किसी एक रिफ्यूजी कैम्प चलने के लिए प्रेरित नहीं किया तो क्यों नहीं किया ?

अमरीका हमें विस्थापितों के लिए सहायता दे रहा है और पाकिस्तान को हथियार दे रहा है। एक ही अमरीका के दो रूप ये हैं। मैं जानना चाहता हूं कि अमरीका के रवैये के विरुद्ध अपना रोष प्रकट करने के लिए विदेश मन्त्री ने कोई कदम उठाया है ? विदेश मन्त्री के आगमन पर जो खुशी जाहिर की गई थी वह गम में बदल गई है और गम जो है वह आज गुस्से का रूप ले रहा है। यह गुस्सा इस सारे सदन में ही नहीं बल्कि देश के सभी भागों में व्यक्त किया जा रहा है। इस गुस्से को एक ठोस आचरण का रूप देने के लिए क्या विदेश मन्त्री यह घोषणा करने के लिए तैयार हैं कि अगर अमरीका पाकिस्तान को हथियार देना बंद नहीं करेगा तो विस्थापितों के लिए जितनी भी मदद अमरीका देने के लिए तैयार हैं हम उसको नहीं लेंगे, हम उनको वापिस कर देने ? घुटनों के बल रोगने से अच्छा है कि अपने पैरों पर लड़ा हो कर हम लड़ते- लड़ते मर जायें।

SHRI SWARAN SINGH : The reply to the first question is "yes". To the second question also the answer is "yes". Dr. Kinsinger said that he was too busy and

that he cannot go to see the refugee camps. Regarding his third question, rather suggestion that in view of the continued policy of the United States Government regarding supply of arms to Pakistan whether I can now declare that I will not accept any aid for refugees, I am sorry, I cannot make such a declaration at the present moment.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : विरोध पत्र लिखित भेजा गया है अमरीका को और यदि हा, तो उसका स्वरूप क्या है और वह कब भेजा गया है ?

SHRI SWARAN SINGH : Yes, this was given on the 27th June 1971.

श्री फूल चन्व वर्मा : यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके ऊपर कम से कम दो घंटे की चर्चा होनी चाहिये। यह हमारे देश के लिए जीवन मरण का प्रश्न है। पूरे सदन की इच्छा है कि इस पर दो घन्टे की चर्चा हो।

MR. SPEAKER : If the rules permit it, I have no objection to allowing it.

12.37 hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE

REVIEW AND REPORT OF HINDUSTAN LATEX LTD. AND PREVENTION OF FOOD ADULTERATION (AMD.) RULES

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY PLANNING (SHRI D. P. CHATTOPADHYAYA) : I beg to lay on the Table—

(1) (i) Review by the Government on the working of the Hindustan Latex Limited, New Delhi, for the year 1969-70.

(ii) Annual Report of the Hindustan Latex Limited, New Delhi, for the year 1969-70 along with the audited Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General thereon. [Placed in Library, See No. LT-638/71.]